>

Title: Need to provide compensation to farmers whose lands have been acquired for construction of new railway line in Etawah Parliamentary Constituency.

श्री प्रेमदास (इटावा): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के रेल मंत्रालय का ध्यान एक महत्वपूर्ण बिन्दु पर आकृष्ट करना चाहता हूं। बहुत दिनों बाद रेल मंत्रालय का माल रेल कॉरीडोर दिल्ली से कोलकाता के बीच बनने जा रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है। जनसंख्या बढ़ गयी, देश का विकास हो रहा है। नयी रेल लाईन बनाना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन, मैं रेल मंत्रालय से यह मांग करता हूं कि जो शहर के किनारे महत्वपूर्ण जमीन थी, उसका उचित मुआवजा वहां के किसानों को नहीं दिया जा रहा है। जो वर्ष 2006 में रेट थी, वर्ष 2012 में उसी के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। किसान भुखमरी पर है। किसान की पूंजी खेती होती है। जब खेती ही नहीं रहेगी तो किसान क्या करेगा?

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसानों की जमीन का उचित रेट दिया जाए। रेल मंत्रालय ने दिनांक 16.07.2010 को एक सर्कुलर जारी किया कि हर परिवार को जिसकी जमीन गयी, उसको एक नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा, मैं कहना चाहूंगा कि किसानों की बगैर सहमति के उनकी जमीन ली जा रही है। किसानों की जमीन पर उनका नाम पृथक् करके उस पर रेल मंत्रालय का नाम दर्ज़ किया जा रहा है। यह बहुत बड़ा अन्याय है। इसे रेल मंत्रालय गंभीरता से ले। अगर यह मामला ठीक नहीं किया गया तो किसान आंदोलन के लिए तैयार है। वह भुखमरी पर आ गया है। इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।